

द पब्लिक मैटर

संपादक : जीवन सिंह

THE PUBLIC MATTER

चंपावत से प्रकाशित

● वर्ष - 01

● अंक-06

● चंपावत

● सोमवार 03 अगस्त 2026

● पृष्ठ-4

● मूल्य: 1/- रूपया

मैरोली और बडपास में आन्तरिक मार्गों हेतु 3.89 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किस्त के तौर पर 1.87 करोड़ स्वीकृत'

(द पब्लिक मैटर ब्यूरो)

मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन द्वारा जनपद चम्पावत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मैरोली एवं ग्राम पंचायत बडपास में आन्तरिक मार्गों के इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा नव-निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना हेतु कुल 3.89 करोड़ की लागत के सापेक्ष प्रथम किस्त के तौर पर 1.87 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से दोनों ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण और दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की मुख्यधारा को पहुंचाना



शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्था और विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत मैरोली एवं बडपास में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने

का कार्य बिना किसी विलंब के शुरू किया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता और मानकों से किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सुदूरवर्ती क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, सेलागाड-कोटकेन्द्री संपर्क मार्ग हेतु 40.53 लाख की स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने और स्थानीय नागरिकों के आवागमन को सुगम बनाने की प्राथमिकता के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

इसी क्रम में जनपद के अंतर्गत सेलागाड से कोटकेन्द्री तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किए जाने हेतु

40.53 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

इस सम्पर्क मार्ग के बन जाने से क्षेत्रवासियों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताओं तक ग्रामीणों की पहुंच और अधिक सुलभ होगी।

मनीष कुमार ने कहा कि सुदूरवर्ती गांवों को मुख्य धारा और पक्की सड़कों से जोड़ना शासन-प्रशासन की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएं समय से पूर्ण कर धरातल पर शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाए।

79.44 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, प्रथम किस्त के रूप में 47.664 लाख रुपये जारी'

(द पब्लिक मैटर ब्यूरो) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा संख्या-259/2026 के क्रम में जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तामली से रुपालीगाड़ होते हुए सीम तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 79.44 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 47.664 लाख रुपये जारी किए गए हैं। शासन के अनुसार कार्य का मानकों एवं वित्तीय जाएगा। कार्य प्रारम्भ तकनीकी स्वीकृतियां निर्माण कार्य की समयबद्धता सुनिश्चित पर योजना से संबंधित का सूचना बोर्ड भी जिलाधिकारी मनीष मुख्यमंत्री के नेतृत्व में को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, विकास कार्यों को गति मिलेगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच और अधिक सुगम होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यों का नियमित अनुश्रवण करते हुए निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।



आदर्श चम्पावत की दिशा में एक और सशक्त पहल: जिलाधिकारी

महिला उद्यमिता को मिला बढ़ावा, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ा महत्वपूर्ण कदम'

(द पब्लिक मैटर ब्यूरो) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आदर्श चम्पावत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में जनपद में महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार ने विकास भवन परिसर में महिला समूह द्वारा संचालित फूड कैंटीन का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत डाइजिटाईड निवासी श्रीमती रितु कुलेठा को अनटायड फंड से 65,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई, जिसके माध्यम से उन्होंने फूड कैंटीन की स्थापना कर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। जिलाधिकारी ने रिबन काटकर कैंटीन का शुभारंभ किया तथा महिला उद्यमी को शुभकामनाएं देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आत्मनिर्भर भारत की मजबूत पहचान बन रही हैं। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें सम्मानजनक स्वरोजगार के



अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने महिलाओं से सकारात्मक कार्यों के माध्यम से समाज में प्रेरणास्रोत बनने का आह्वान किया।

अपर परियोजना निदेशक (एपीडी) विष्मी जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाकर स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभाग हरसंभव सहयोग प्रदान करता रहेगा।

कार्यक्रम में विकास भवन के अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े कार्मिक, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। महिला समूहों ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन-प्रशासन के सहयोग से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित केलपाल बाबा स्वयं सहायता समूह भी महिला उद्यमिता की प्रेरक मिसाल बनकर उभरा है। समूह की सदस्य श्रीमती पार्वती सफलतापूर्वक पार्वती टिफिन सर्विस का संचालन कर रही हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न कार्यक्रमों एवं आयोजनों के लिए कैंटरिंग एवं पार्टी ऑर्डर की सेवाएं भी प्रदान कर रही हैं।

जीवन सिंह

संपादकीय



साइबर अपराधियों का शिकंजा

संयुक्त राष्ट्र की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के नागरिकों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिये साइबर अपराधियों ने 114 अरब डॉलर तक का नुकसान पहुंचाया है। यानी साइबर अपराधियों ने भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर एक समानांतर आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर दिया है। दरअसल, आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग करके साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट, डीपफेक, क्रिप्टोकॉर्सेसी व फर्जी निवेश के प्रलोभन तथा विदेशों में नौकरी के सब्जबाग दिखाकर लोगों को लूट रहे हैं। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। गाढ़े-बगाड़े बुजुर्ग व सेवानिवृत्त अधिकारियों की जीवन-भर की जमा पूंजी लूटने के मामले भारत में प्रकाश में आते रहते हैं। दरअसल, पुरानी पीढ़ी डिजिटल दुनिया की जटिलताओं और प्रलोभनों से इन अपराधियों के बुने जाल में फंस जाती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि आपराधिक कानूनों में 'डिजिटल अरेस्ट' को औपचारिक रूप से परिभाषित किया जाए। साथ ही इसे कड़ी सजा वाले एक अलग अपराध के तौर पर घोषित किया जाए। निश्चित रूप से डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते अपराधों के चलते ऐसे मामलों में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। दरअसल, डिजिटल अरेस्ट में अपराधी ऑडियो व वीडियो कॉल के जरिये पुलिस, अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारी, अदालत के कर्मचारी तथा सरकारी अधिकारी बनकर पीड़ितों को इतना आतंकित करते हैं कि वे भयभीत होकर अपनी जीवनभर की जमा पूंजी लुटवा बैठते हैं। बीते साल भी अंबाला के एक ऐसे ही जोड़े के पत्र के आधार पर कोर्ट ने स्वतंत्र संज्ञान लिया था। हाल में संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारतीयों ने विभिन्न साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 22,845 करोड़ रुपये गंवा दिए। इस दौरान साइबर अपराध की करीब 22 लाख घटनाएं सामने आई थीं।

2.64 करोड़ रूपए की लागत से 2 किलोमीटर सड़क निर्माण से ग्रामीणों को मिलेगा बेहतर आवागमन'

मुख्यमंत्री की घोषणा को मिली प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति'
'चम्पावत-तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी मोटर मार्ग का होगा सुधारीकरण एवं डामरीकरण'

(द पब्लिक मैटर ब्यूरो) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अंतर्गत जनपद चम्पावत की विधानसभा चम्पावत क्षेत्र में चम्पावत-तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य को शासन से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उत्तराखण्ड शासन के लोक निर्माण अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार 2.0 किलोमीटर लंबाई वाले इस सड़क कार्य के लिए 2.64 करोड़ (264.24 लाख रुपये) की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्य प्रारंभ करने हेतु प्रारंभिक धनराशि भी अवमुक्त की गई है। इस सड़क के सुधारीकरण एवं डामरीकरण से क्षेत्र के ग्रामीणों को वर्षभर सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति प्राप्त होगी। यह परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

नेतृत्व में जनपद में सड़क संपर्क सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष प्राथमिकता के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चम्पावत-तामली मोटर मार्ग



जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि मा. मुख्यमंत्री के

से मुख्य तोक कारी मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण की स्वीकृति से क्षेत्रवासियों को बेहतर एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप किया जाए। साथ ही सभी आवश्यक स्वीकृतियां, वन भूमि संबंधी औपचारिकताएं तथा अन्य वैधानिक प्रक्रियाएं पूर्ण करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाए, ताकि निर्माण कार्य समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके।

लोहाघाट में 24 लाभार्थियों को मिली मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से राहत राशि'

लाभार्थियों को वितरित किए 5-5 हजार रुपये के चेक'

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संवेदनशील पहल के तहत जनपद के पात्र एवं जरूरतमंद नागरिकों को त्वरित राहत पहुंचाने की दिशा में शुक्रवार को तहसील परिसर लोहाघाट में सहायता राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उप जिलाधिकारी लोहाघाट श्रीमती नीतू डांगर ने जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी मौजूदगी में, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से स्वीकृत 24 लाभार्थियों को राहत राशि के चेक प्रदान किए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय सरकारी योजनाओं और सहायता राशि का लाभ आमजन तक अत्यंत सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। लाभार्थियों को दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर न काटने पड़ें, इसी सोच के साथ सीधे पात्र व्यक्तियों



को चेक सौंपे गए हैं।

उप जिलाधिकारी नीतू डांगर ने बताया कि जन-जन की सरकार अभियान, जनता मिलन कार्यक्रम तथा जन समर्पण पोर्टल के माध्यम से प्राप्त

आवेदनों का परीक्षण किया गया। शासन के निर्धारित मानकों पर खरे उतरे पात्र व्यक्तियों को ही यह सहायता प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी,

आकस्मिक दुर्घटनाओं और आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष एक बड़ा संबल है।

बिना किसी जटिल प्रक्रिया के सीधे

सहायता राशि प्राप्त होने पर सभी लाभार्थियों ने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और जिला प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त किया। लाभार्थियों ने कहा कि संकट की इस घड़ी में मिली यह समयबद्ध मदद उनके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है।

24 लाभार्थियों को मिला आर्थिक सहायता का लाभ

सहायता राशि प्राप्त करने वालों में भारती पांडे, हेमंत पांडे, कोकिला देवी, चंद्रशेखर राय, हेमचंद्र जोशी, मंजू राय, बची सिंह महर, मीना देवी, स्मृति पांडे, सुरेश डेविड, गोविंद देवी, रेखा पाटनी, दीपक कुमार, आनंदी देवी, कमला देवी, रेनू कालाकोटी, सुनीता देवी, नंदा देवी, रेवाधर, इनायत अहमद, ताहिर अहमद, सुरेश चंद्र भट्ट, पुष्पा देवी तथा हेमा जोशी शामिल हैं। इन सभी 24 लाभार्थियों को 5,000-5,000 की धनराशि का चेक सौंपा गया।

कार्यक्रम नगर पालिका परिषद लोहाघाट अध्यक्ष गोविंद वर्मा, भाजपा प्रदेश महामंत्री

मुख्यमंत्री की घोषणा धरातल पर, तामली क्षेत्र में 14.57 करोड़ की पेयजल योजना का कार्य शुरू'

भूमि पूजन के साथ 1457.21 लाख रुपये
लागत की तामली ग्राम समूह पंपिंग
पेयजल योजना का शुभारंभ, क्षेत्रवासियों
को मिलेगा नियमित पेयजल'

सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पेयजल
जैसी आधारभूत आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए सरकार
ने इस महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे क्षेत्र
के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह
योजना ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ-साथ

कि 1457.21 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली इस
पंपिंग पेयजल योजना के अंतर्गत आधुनिक तकनीक के माध्यम
से जलस्रोत से पानी उठाकर ओवरहेड टैंक एवं वितरण प्रणाली
के जरिए प्रत्येक लाभार्थी गांव तक पानी पहुंचाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

आदर्श चम्पावत

श्री पुष्कर सिंह धामी
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में शामिल

₹1457.21 लाख

की लागत से तामली ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का

कार्य प्रारम्भ होने पर समस्त ग्रामवासियों की ओर से

माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं अभिनन्दन!

निवेदक - समस्त तामली क्षेत्रवासी

'मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पाण्डेय एवं दर्जा राज्य मंत्री श्री मुकेश महराना की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ भूमि पूजन एवं कार्यारंभ'

(द पब्लिक मैटर ब्यूरो)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं के क्रम में स्वीकृत 1457.21 लाख रुपये की लागत वाली तामली ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना के कार्यारंभ अवसर पर शुक्रवार को तामली क्षेत्र में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पाण्डेय, दर्जा राज्य मंत्री मुकेश महराना, पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता श्री अशोक स्वरूप, जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों ने पूजा-अर्चना कर योजना के सफल एवं समयबद्ध निर्माण की कामना की।

कार्यक्रम में पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता अशोक स्वरूप ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना के पूर्ण होने के बाद तामली क्षेत्र के अनेक गांवों के लोगों को वर्षभर स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगी।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक मूलभूत

महिलाओं एवं बच्चों को पेयजल लाने में होने वाली कठिनाइयों से भी राहत दिलाएगी।

इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री मुकेश महराना ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि तामली क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से निर्माण कार्य पूर्ण करने का आह्वान किया।

पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता अशोक स्वरूप ने बताया

निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाएगा।

कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना के शुरू होने से क्षेत्र की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा तथा ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने योजना के शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन की अपेक्षा व्यक्त की।

पशु चिकित्सा शिविर हुआ आयोजित, 21 पशुपालकों के 58 पशुओं का हुआ उपचार व औषधि वितरण'

जिलाधिकारी मनीष कुमार के कुशल निर्देशन में राजकीय सचल पशु चिकित्सालय चम्पावत द्वारा चम्पावत ब्लॉक के दूरस्थ ग्राम केल्यूडा, ढोलंगा एवं चोड़ाराजपुरा में विशेष पशु चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया।

इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के द्वार तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना और पशुधन को सुरक्षित रखना रहा। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. वसुंधरा गर्ब्याल ने बताया कि आयोजित शिविर में कुल 21 पशुपालकों के 58 पशुओं का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान बीमार पशुओं का मौके पर ही उचित उपचार करने के साथ-साथ पशुपालकों को आवश्यक औषधियाँ निरुशुल्क वितरित की गईं। उन्होंने बताया कि इस शिविर में सचल पशु चिकित्सा अधिकारी, सचल पशु चिकित्सा फार्मसी अधिकारी एवं वाहन चालक सहित विभागीय टीम ने पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी सेवाएँ दीं, जिससे स्थानीय पशुपालकों को काफी राहत मिली है।

जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय से रोडवेज तक किया व्यापक निरीक्षण, सड़क, पेयजल, पार्किंग व सफाई व्यवस्था शीघ्र दुरुस्त किये जाने के दिए निर्देश

‘गड्डामुक्त सड़क, सुचारु जल निकासी एवं समयबद्ध निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के दिए निर्देश’

(द पब्लिक मैटर ब्यूरो)

जनपद में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शनिवार को जिला चिकित्सालय से रोडवेज स्टेशन तक राष्ट्रीय राजमार्ग, निर्माणाधीन पार्किंग स्थलों, पेयजल पाइपलाइन, नालियों, सिटी सेंटर तथा सफाई व्यवस्था का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की तथा सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह-जगह बने गड्डों को तत्काल भरने, ब्लैकटॉप कराने तथा सड़क किनारे जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने



कहा कि बरसात के दौरान सड़क पर लगातार बह रहे पानी से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, इसलिए इसके स्थायी समाधान के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए, जिससे आमजन को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन मिल सके।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन की शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश देते हुए कहा कि रिसाव के कारण पेयजल की बर्बादी के साथ-साथ सड़कें भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को निर्माणाधीन पार्किंग कार्यों में तेजी लाने तथा ग्रामीण

निर्माण विभाग (आरडब्ल्यूडी) को जिला चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन पार्किंग का कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने नगर पालिका को नालियों की नियमित सफाई, झाड़ियों की कटाई, सड़क किनारे पड़े मलबे एवं कंक्रीट को हटाने तथा अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर की स्वच्छता एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित निगरानी आवश्यक है।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मार्ग में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान



का भी निरीक्षण किया। उन्होंने रेट लिस्ट एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संचालक को सख्त निर्देश दिए कि दुकान के आसपास किसी भी व्यक्ति को शराब का सेवन न करने दिया जाए। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासन एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए। इसके उपरान्त जिलाधिकारी ने रोडवेज हेतु प्रस्तावित सिटी सेंटर का निरीक्षण कर सम्बंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित से जुड़े सभी कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की

जाएगी। संबंधित विभाग नियमित समन्वय के साथ कार्य करें तथा आमजन को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

निरीक्षण के दौरान जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल, अधिशासी अभियंता सीएनडीएस गिरीश पंत, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग विभोर गुप्ता, अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग सुनील दत्ताल, जल संस्थान के अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका भरत त्रिपाठी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के विज़न से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं: चंपावत में नाबार्ड और आजीविका मिशन के सहयोग से शुरू हुई दीदी कैफे पहल

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहलरू दीदी कैफे के संचालन हेतु चार महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किए गए 50,000 की लागत वाले मोबाइल कार्ट्स

(द पब्लिक मैटर ब्यूरो)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एकल महिला स्वरोजगार योजना और श्लखपति दीदी योजना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम निरंतर चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में, ग्रामीण विकास विभाग और नाबार्ड (छ।उ।त्व) के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन एवं ग्राम विकास विभाग की इस संयुक्त पहल के तहत आरसेटी से फास्ट फूड का प्रशिक्षण प्राप्त सशक्त स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 50,000 मूल्य



के मोबाइल फूड कार्ट्स प्रदान किए गए। शनिवार को जिला कार्यालय परिसर में जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा चार महिला स्वयं सहायता समूहों की लाभार्थियों को उनके उपयोग हेतु ये कार्ट्स सौंपे गए। ये लाभार्थी महिलाएं मुख्य व्यावसायिक स्थलों जैसे यात्रा मार्गों, डिग्री कॉलेजों, अस्पतालों और राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रमुख स्थानों पर दीदी कैफे के नाम से इन मोबाइल कार्ट्स का संचालन करेंगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि नाबार्ड (वित्त पोषित) के सहयोग से महिलाओं को आर्थिक संबल और सुदृ

ढ़ीकरण प्रदान करने का यह विशेष प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देशों में शुरु की गई यह पहल आने वाले समय में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। भविष्य में जिले के अन्य प्रमुख स्थानों का चयन कर इस योजना का और अधिक विस्तार किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सहायक परियोजना निदेशक सुश्री विमी जोशी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और नाबार्ड के संयुक्त सहयोग से स्वयं सहायता



समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चंपावत में यह विशेष पहल शुरु की गई है। इसके तहत आजीविका संवर्धन

के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए ये मोबाइल फूड कार्ट्स महिलाओं को शदीदी कैफे संचालन हेतु उपलब्ध कराए गए हैं।

द पब्लिक मैटर

स्वामी, प्रकाशक **जीवन सिंह** द्वारा मुद्रक योगेश कुमार, विशाल दर्पण प्रेस 50/51, नारी शिल्प मंदिर मार्ग, चकराता रोड देहरादून, उत्तराखंड - 248001 से मुद्रित तथा मकान नंबर 93, जिला पंचायत गेट, पिथौरागढ़ रोड, कर्नाटक अस्पताल के पास, चंपावत, उत्तराखंड - 262523 से प्रकाशित।

संपादक : **जीवन सिंह** - 7500344495

PRGI No. UAHIN/26/A5401

Email: jeewanbisht888@gmail.com

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी है। समस्त विवाद चंपावत न्यायालय के अधीन होंगे।

“इस प्रकाशन की सामग्री के संबंध में समस्त उत्तरदायित्व प्रकाशक एवं संपादक का होगा। प्रिंटिंग प्रेस केवल मुद्रण सेवा प्रदाता है।”